बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 191 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 15 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली सरकार-एमसीडी दफ्तरों का बदला समय, सरकारी कर्मचारियों पर 1 साल तक लगी ये पाबंदी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए 90 दिनों का विशेष जन-अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान चलाएगी और राजधानी को एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में विकसित करने की कोशिश करेगी. रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि वह 1 साल तक विदेश नहीं जा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि अलग-अलग सरकारी संस्थानों के दफ्तरों का समय भी अलग-अलग रखा जाएगा.

एनआईए ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों में आरोपपत्र

नई दिल्ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने 10 नवंबर, 2025 को हुए इस हमले में कथित संलिप्तता के लिए 10 लोगों को नामजद किया है।

इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। एनआईए के अनुसार, सहित सभी 10 आरोपी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे, जिसे अल-कायदा से प्रेरित संगठन बताया गया है। मुख्य आरोपी उमर उन नबी की इस धमाके में मौत हो गई थी। उसके अलावा नौ अन्य आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। डॉ. नबी के अलावा, चार्जशीट में नामित अन्य व्यक्तियों में आमिर राशिद मीर, जसीर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन

सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार शामिल हैं। एनआई की जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित मेडिकल प्रोफेशनल थे। 2022 में श्रीनगर में हुई एक गुप्त बैठक में उन्होंने "AGuH Interim" नाम से संगठन को फिर सक्रिय किया और "peration Heavenly Hind" शुरू किया था। एनआईए की जांच से पता चला कि "Operation Heavenly Hind" के तहत, आरोपियों ने नए सदस्यों की भर्ती की, AGuH की हिंसक जिहादी विचारधारा का सक्रिय रूप से प्रचार किया, हथियार और गोला-बारूद जमा किया, और बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर विस्फोटक बनाए। एजेंसी ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल TATP विस्फोटक आरोपियों ने खुद तैयार किया था। एनआईए की जांच से यह भी पता चला कि आरोपी प्रतिबंधित हथियारों की अवैध खरीद में भी शामिल थे, जिनमें एक-ч-47 राइफल, एक क्रिनकोव राइफल और कारतूसों वाली देसी पिस्तौलें शामिल थीं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न ऑलाइन और ऑनलाइन स्रोतों से प्रयोगशाला उपकरण खरीदे थे। यह चार्जशीट एक विस्तृत जांच पर आधारित है, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र तक फैली हुई है। इसमें 588 मौखिक गवाहियों, 395 से अधिक दस्तावेजों और 200 से अधिक जब्त की गई चीजों के रूप में विस्तृत सबूत शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और NIA उन फरार आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी रखे हुए है, जिनकी भूमिका जांच के दौरान सामने आई थी।

इन्फ्लुएंसर द स्किन डॉक्टर गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर किए थे आपत्तिजनक पोस्ट

नई दिल्ली । दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने कारोबारी संजय कपूर की मौत के बाद कपूर परिवार को निशाना बनाते हुए कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नीलम सिंह को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बुधवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में कपूर परिवार की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि इन्फ्लुएंसर ने कपूर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मानहानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री÷ साझा की थी। पुलिस ने बताया कि डॉ. नीलम सिंह, जिन्हें ऑनलाइन ÷द स्किन डॉक्टर÷ के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है, आरोपों के प्रारंभिक सत्यापन के बाद उन्हें ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांचकर्ता संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहे हैं और सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा पोस्ट किए गए कुछ ट्वीट आपत्तिजनक प्रकृति के थे और उनसे परिवार को मानसिक कष्ट पहुंचा। शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। चोरी, मानहानि और आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है पुलिस इस बात की जांचकर्ता इस बात की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्या कोई अतिरिक्त सामग्री अपलोड की गई थी या बाद में उसे हटा दिया गया था। पुलिस इस मामले से संबंधित बयान दर्ज करने और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं। अधिकारी ने कहा कि जांच के हिस्से के रूप में, सामग्री पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा सकती है।

पीएम मोदी की अपील का असर- एनडीएमसी में 33 फीसदी कर्मी करेंगे वर्क फॉम होम, व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू

दिल्ली । दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 33 फीसदी कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा क इसका मकसद अनावश्यक आवागमन कम कर ईंधन की बचत सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत चिन्हित विभागों के समूह बी और समूह सी के अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी। विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की क्रमवार ड्यूटी सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयी कामकाज और जनसेवाएं प्रभावित न हों। दूर-दराज इलाकों से निजी वाहनों के जरिए आने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। एनडीएमसी ने स्पष्ट किया कि घर से काम करने वाले कर्मचारियों को आधिकारिक संचार माध्यमों पर उपलब्ध रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा। वहीं कई जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इनमें सफाई एवं जनस्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं, बिजली और जल आपूर्ति कर्मचारी, उद्यान विभाग, अभियांत्रिकी एवं रखरखाव दल, प्रवर्तन और निरीक्षण टीमें तथा नियंत्रण कक्ष और आपदा प्रतिक्रिया कर्मचारी शामिल हैं। एनडीएमसी ने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। वित्त एवं लेखा विभाग को दिल्ली मेट्रो कार्ड के जरिए यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो और डीटीसी अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी।

अपमानजनक आरोप लगाए...केजरीवाल-सिसोदिया की और बढ़ेगी मुश्किल, जस्टिस शर्मा ने कहा- अवमानना की कार्यवाही शुरू करेंगे

नई दिल्ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट करने के आरोप में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा। न्यायालय आज शाम 5 बजे विस्तृत आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि आज मुझे एमिकस (अदालती वकील) नियुक्त करना था और मैंने इसके लिए प्रयास भी किए, कुछ वरिष्ठ वकीलों ने इसके लिए सहमति भी दे दी। लेकिन इसी बीच मुझे पता चला है कि कुछ प्रतिवादियों द्वारा मेरे और इस न्यायालय के खिलाफ बेहद अपमानजनक, बेहद अवमाननापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की जा रही है और मैं चुप नहीं रह सकती। मैंने कुछ प्रतिवादियों और

कुछ अन्य अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि वे न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद खत्म हो गई है। इसलिए मैंने महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का फैसला किया है। केजरीवाल के बाद, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी न्यायमूर्ति शर्मा को पत्र लिखकर सूचित किया कि वे भी उनकी अदालत में बिना वकील के पेश होंगे। न्यायमूर्ति शर्मा ने इससे पहले सीबीआई की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश शर्मा ने इस मामले से खुद को अलग करने की याचिका खारिज करते हुए कहा अगर मैं इन (खुद को अलग करने की) याचिकाओं को स्वीकार करती, तो यह एक चिंताजनक मिसाल कायम करता।

उन्होंने यह भी कहा कि पक्षपात या भेदभाव का हर अप्रमाणित और निराधार आरोप न केवल किसी एक न्यायाधीश पर लगाया जाता है, बल्कि न्यायपालिका की सामूहिक अखंडता पर भी कलंक लगाता है। न्यायाधीश ने कहा कि जब भी जरूरत होगी, अदालत अपने और न्यायपालिका के लिए खड़ी होगी, भले ही यह मुश्किल लगे।

सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एलान, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन रहेगा वर्क फॉम होम

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में दो दिन वर्क फॉर्म होम रहेगा। प्राइवेट कंपनियों को भी हफ्ते में दो दिन वर्क फॉर्म होम के लिए कहा जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मानते हुए अपने काफिले में 60 प्रतिशत की कटौती की है। सीएम के काफिले में अब सिर्फ चार गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 ईवी हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी मंत्रियों के वाहनों में कटौती की गई है। जहां पर संभव होगा हम लोग सार्वजनिक वाहन का भी उपयोग करेंगे।

जिनका 200 लीटर पेट्रोल की लिमिट थी, उनके लिए 160 लीटर होगी। जिन्हें ढाई सो लीटर पेट्रोल मिलता था, उन्हें अब 200 लीटर दिया जाएगा।

दफ्तरों का समय भी बदला

हर सोमवार को अधिकारी और कर्मचारी जितना संभव होगा, मेट्रो का उपयोग करेंगे। कार्यालय का समय बदल गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय का समय अब 10:30 से शाम सात बजे तक रहेगा। दिल्ली नगर निगम के सभी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम साढ़े 5:00 बजे तक काम करेंगे।

दिल्ली सरकार अपनी फिजिकल बैठकों में कटौती करेगी और 50फीसदी बैठकें ऑनलाइन करेंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी अगले एक साल तक विदेशी टूर नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता से अपील की कि सभी लोग सप्ताह में एक दिन बगैर अपने वाहन के चलें। दिल्ली सरकार अगले छह माह तक कोई भी वाहन नहीं खरीदेगी। दिल्ली सरकार की 29 कॉलोनी के लिए 58 बसों का एक रूट बनाया गया है, जो बसें उनके कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक के लिए चलेंगी।

शेष दुनिया के लिए अहम

सफल कारोबारी से राजनेता बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हर रिश्ते को फायदे और नुकसान के नजरिये से देखते है, लेकिन कूटनीतिक इंजीनियर समझे जाने वाले चीन के अपने दौरे को लेकर उन्होंने केवल इतना भर कहा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, वैश्विक रणनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। चूंकि अमेरिका और चीन एक दूसरे के सहयोगी और प्रतिस्पर्धी दोनों समझे जाते है, इसलिए लगभग एक दशक के अन्तराल पर हुई उनकी यह यात्रा के कूटनीतिक मायने अहम समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी इस मुलाकात की सफलता और विफलता का असर पूरी दुनिया पर निःसंदेह पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले साल यानी अक्टूबर 2025 में जब आखिरी बार ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, तब उनके बीच मुख्य मुद्दा टैरिफ था, लेकिन अब बदलते वैश्विक हालात में जाहिर तौर पर ईरान भी होगा। क्योंकि पश्चिम एशिया संकट ने दोनों देशों के लिए मुश्किलें बढ़ाई है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि आपसी तनाव के बावजूद वे सहयोग का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। चूंकि लगभग एक दशक बाद यानी 2017 के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 2026 में चीन पहुंचा है। हालांकि, टैरिफ वॉर की वजह से माना जाता है कि ट्रंप का रुख पेइचिंग को लेकर कठोर है। समझा जाता है कि अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने यानी ट्रंप ने चीन से होने वाले आयात पर टैरिफ की घोषणा की थी। जबकि दूसरे टर्म में वह इस लड़ाई को और आगे ले गए और 125% तक भारी भरकम टैरिफ तक जड़ दिया। हालांकि दुनियावी रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीनी नियंत्रण की वजह से आखिरकार ट्रंप को झुककर समझौता करना पड़ा था, अन्यथा उनका कारोबारी हित प्रभावित होता। ऐसे में टैरिफ वॉर भले थम गई हो, पर अमेरिका और चीन के बीच की पारस्परिक होड़ कायम है और वह नित्य नए स्वरूप में उभरकर सामने आ ही जाती है। चूंकि दोनों देश एक-दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर इतना नहीं जिससे बात ज्यादा बिगड़े। हाल के अमेरिका/इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान भी कुछ यही देखने को मिला है। भले ही ईरान को आर्थिक व सामरिक मदद के आरोप में अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, और चीन ने भी पलटवार करते हुए वॉशिंगटन की नीतियों का विरोध किया, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में रखकर हुआ। इसकी ठोस वजह उनकी आपसी निर्भरता और पारस्परिक जरूरत भी है, जिसे समझने की जरूरत है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि चीन के लिए अमेरिका आज भी सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि इस साल चीनी निर्यात में करीब 10% की कमी आई है। चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह झटका है। दिलचस्प बात तो यह है कि खाड़ी देशों में भी चीन का निर्यात घटा है। मसलन, तेहरान (ईरान) का सबसे बड़ा तेल खरीदार होने के नाते भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। लिहाजा चीन चाहता है कि युद्ध जल्दी थमे। भारत की भी यही सोच है। वहीं दूसरी ओर, ट्रंप को ईरान पर समर्थन और निवेश के लिए चीन चाहिए। इसीलिए वह अपने साथ कई बड़े उद्यमियों को लेकर बीजिंग पहुंचे है। चूंकि अमेरिका इस दौरे से बड़ी डील की उम्मीद कर रहा है, खासकर बोइंग विमानों की। इसलिए आलोचकों को डर है कि कहीं ताइवान पर ट्रंप नरम न पड़ जाएं। अमेरिकी हित में वह ऐसा कर सकते है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि इस समय दोनों रस्साकशी नेता घरेलू मोर्चे पर विविध असहज स्थितियों में फंसे हुए हैं। लिहाजा उनकी कोशिश यही होगी कि इस मुलाकात से कुछ बड़ा हासिल किया जाए। यदि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पारस्परिक सहयोग के रास्ते पर बढ़ती है और ईरान में शांति कायम होती है, तो यूक्रेन सहित सभी का फायदा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे पर दुनियाभर की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में स्वाभाविक बात है कि भारत भी अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखेगा। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इससे जुड़े एक सवाल पर कहा भी है कि भारत के कई देशों के साथ रिश्ते है। कई देशों के साथ साझेदारी आगे बढ़ रही है। चूंकि विभिन्न देशों के बीच इस तरह का दौरा होता रहता है और जब भी इस तरह के दौरे होते है तो भारत देखता है कि उसमें क्या बदलाव आया है- या फिर क्या गतिविधियां हुई। ऐसा इसलिए किया जाता है कि राष्ट्रहित के अनुरूप नीतियां संशोधित होती रहें। चूंकि भारत हाल के वर्षों में अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। दूसरी ओर चीन भी भारत का अहम पड़ोसी देश है, जिसके साथ सीमा विवाद के बाद भी रिश्ते व्यवहारिक समझ पर वापस लौट रहे है। ऐसे में दोनों देशों के आपसी संबंध और इस दौरे के निष्कर्ष भी भारत पर असर डालेगा। अमेरिका और चीन के रिश्ते एक लंबे वक्त तक असहजता के दायरे में रहे, जिसके जियोपॉलिटिकल प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा है। ट्रंप का यह दौरा 2017 के बाद हो रहा है। चीन पहुंचने पर बुधवार को ट्रंप का स्वागत उपराष्ट्रपति ने किया, जो 2017 से अच्छा स्वागत होने को दर्शाता है। चीन मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत जानना चाहेगा कि ट्रंप और चिनफिंग के बीच बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला। हाल के वर्षों में प्रशांत महासागर में जिस तरह चीन का प्रभाव बढ़ा है, इसी बैलेंस आफ पावर के मद्देनजर अमेरिका और भारत रणनीतिक और सामरिक मुद्दों पर लगातार नजदीकी स्तर पर काम करते रहे। ऐसे में अमेरिका और चीन अपने सबंधों को अगर फिर से नया आयाम देने का फैसला करते है तो अमेरिका व चीन दोनों के रिश्तों के मुताबिक भारत को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करना होगा।

पेपर लीक-तंत्र 'वीक'

23 लाख छात्र पेपर लीक होने के बाद नीट-यूजी परीक्षा रद्द किए जाने की खबर मिलने के बाद काफी हताश हैं। छात्र खुद को फिर से अनिश्चितता और चिंता के भंवर में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। अब तक एनटीए द्वारा आयोजित 14 राष्ट्रीय परीक्षाओं में से कई बार पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले उजागर हो चुके हैं। इनमें से जेईई मेन्स 2025 उत्तर कुंजी के दोषपूर्ण होने पर प्रश्नपत्र में 12 प्रश्न वापिस लेने पड़े थे। देश में कई भर्ती परीक्षाओं में पहले ही बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद लाखों छात्र राहत महसूस कर रहे थे लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर गेस पेपर और पेपर लीक की चर्चाएं तेज होने लगीं। शुरुआत में तो इसे अफवाह माना गया लेकिन फिर राजस्थान में गिरफ्तारियों और हिरासत की खबरें सामने आने लगीं। मामला इतना बढ़ गया कि पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। परीक्षा रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा असर उन छात्रों पर पड़ा है जो कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। कई छात्र मानसिक दबाव में हैं। अभिभावकों की चिंता यह है कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं तो मेहनती छात्रों का भरोसा कैसे कायम होगा। इसके साथ ही एनटीए के उद्देश्य और कार्यक्षमता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नेशनल टैस्टिंग एजेंसी यानि एनटीए ने दावा किया था कि नीट परीक्षा को पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कराया गया है। सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए है, ताकि किसी भी तरह की नकल या पेपर लीक को रोका जा सके। प्रश्नपत्र भी जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों से भेजे गए थे। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करना निस्संदेह एक बड़ी चुनौती है। इस वर्ष की एनईईटी परीक्षा 550 से अधिक शहरों में लगभग 5,580 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। एनटीए ने प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा उपायों के उपयोग पर जोर दिया है लेकिन परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों के कथित वितरण से पता चलता है कि एक त्रुटिरहित प्रणाली अभी भी दूर की बात है। 2024 एनईईटी विवाद के बाद केंद्र ने एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एजेंसी ने अभी तक समिति द्वारा रेखांकित डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को पूरी तरह से लागू नहीं किया है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश-परीक्षा प्रक्रिया के सभी चरणों में जवाबदेही में सुधार पर अमल करने में ढिलाई बरती है। एनटीए निजी परीक्षा केंद्र संचालकों और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि झारखंड में 2024 एनईईटी परीक्षा सहित कई प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं ने इन विक्रेताओं और कोचिंग उद्योग के बीच संबंधों को उजागर किया है। साथ ही एजेंसी ने बाहरी संचालकों पर दोष मढ़कर विफलताओं के लिए संस्थागत जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। अब तक मिली रिपोर्टों के अनुसार प्रश्नपत्र प्रिंटिंग के समय ही लीक करने वालों के हाथों तक पहुंच चुका था। अगर ऐसा साबित होता है तो यह परीक्षा सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। गैस पेपर में दिए गए प्रश्नों में 120 से ज्यादा प्रश्नपत्र में शामिल प्रश्नों के हूबहू निकले। सोशल मीडिया के जरिये गैस पेपर लाखों छात्रों तक पहुंचे। एनटीए द्वारा जांच सीबीआई को सौंपने के बाद अब धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। भ्रष्टाचार के बाजार में लाखों का लेन-देन भी सामने आ रहा है। प्रतिभाशाली छात्रों के सपने खंडित हो गए हैं लेकिन इस घटना को केवल कानून-व्यवस्था के उल्लंघन तक सीमित करना संस्थागत विफलता की भयावहता को कम आंकना होगा। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर एक गंभीर आरोप है, जिसे देश की कुछ सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। 2017 में परीक्षा को पेशेवर बनाने के उद्देश्य से गठित एनटीए को प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और खंडित राज्य-स्तरीय प्रणालियों की विसंगतियों को दूर करने का दायित्व सौंपा गया था। इसके विपरीत, पेपर लीक और अनियमितताओं के बार-बार लगने वाले आरोपों से इसका रिकार्ड लगातार धूमिल होता रहा है। नवीनतम एनईईटी विवाद दो वर्षों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े दूसरे बड़े विवाद ने उन परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा करने की एजेंसी की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर हजारों युवाओं का भविष्य टिका है। यद्यपि एनटीए ने दुबारा परीक्षा कराने के लिए दुबारा शुल्क और फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत कोखत्म कर दिया है लेकिन बार-बार होने वाले घोटालों ने नीट की वर्तमान उपयोगिता पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि 3 घंटे की परीक्षा में 180 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर किसी युवा को डॉक्टर बनने की योग्यता का आंकलन कैसे किया जा सकता है। कोचिंग संस्थान रटने को ही अधिक महत्व दे रहे हैं। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए एनटीए के पुनर्गठन की जरूरत समझी जा रही है। नीट परीक्षा को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की मांग की जा रही है। अगर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा अपनाई जाती है तो वह सुरक्षित और पारदर्शी होगी। छात्रों को हमें ऐसी प्रणाली प्रदान करनी होगी जोउनकी मेहनत को महत्व दे। परीक्षा में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले जवाबदेही तय करनी होगी। परीक्षा लीक का अर्थ तंत्र 'वीक' (कमजोर) होना ही है।

सम्पादकीय...

गांव से शासन तक

प्रदेश में लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के बीच समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान और ऑनलाइन सेवाओं के संचालन में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती रही। जनपद, तहसील और विकास खण्ड स्तर पर इंटरनेट एवं डेटा संचार की कमजोर व्यवस्था के कारण ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रभावी संचालन प्रभावित होता था, जिससे आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यू.पी. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपीस्वान) जैसी महत्वाकांक्षी योजना को विकसित किया गया, जिसने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मईटी), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान के अंतर्गत प्रदेश में यूपीस्वान का संचालन प्रारम्भ किया गया। यह नेटवर्क प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। प्रारम्भिक चरण में भारत सरकार के सपोर्ट से संचालित इस योजना को जनवरी 2015 के बाद राज्य सरकार द्वारा इस पर व्यय धनराशि का स्वयं वहन किया गया तथा सितंबर 2019 तक इसका संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से कराया गया। इसके पश्चात यूपीस्वान-2.0 का क्रियान्वयन ओपेक्स मॉडल पर एमपीएलएस सिस्टम के तहत किए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (सिस्टम इंटीग्रेटर) के रूप में मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड का चयन किया गया तथा दिनांक 04 अप्रैल 2019 को अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। यूपीस्वान-2.0 का संचालन 01 अक्टूबर 2019 से प्रारम्भ किया गया। यूपीस्वान-2.0 के अंतर्गत प्रदेशभर में कुल 885 स्वॉन पॉप केन्द्र स्थापित किए गए है, जिनमें 1 राज्य मुख्यालय, 75 जनपद, 235 तहसील एवं 574 विकास खण्ड मुख्यालय शामिल है। राज्य मुख्यालय प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (पॉप) पर 5 जीबीपीएस तथा शेष 884 पॉपस पर 10 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ उपलब्ध कराई गई है। इस नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों के जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। वर्तमान समय में यूपीस्वान-2.0 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही बैण्डविड्थ का उपयोग विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, भू-लेख, जनसुनवाई, छात्रवृत्ति, कृषि सेवाएं सहित अनेक महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं इसी नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रही हैं। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, गति और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा आम नागरिकों को घर के निकट ही डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में नियमित प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसे चुनाव आदि के दौरान भी संबंधित विभागों द्वारा यूपीस्वान नेटवर्क का प्रभावी उपयोग किया जाता है।

मई के वो चार दिन

22 अप्रैल, 2025 कश्मीर में पहलगाम के नजदीक पर्यटन स्थल बैसरन में तीन सशस्त्र आतंकवादियों ने वहां लोगों का धर्म पूछ और अत्यन्त क्रूरता से 26 लोगों की हत्या कर दी। हमारी जमीन पर पहले भी हमले हुए हैं, पर ऐसा जघन्य हमला पहले नहीं हुआ जब परिवार के सामने हिन्दू मर्दों को अलग कर गोली मार दी गई। सारा देश तड़प उठा। तभी स्पष्ट हो गया था कि इसका बदला लिया जाएगा। 7 मई 2025 की सुबह 1.05 बजे भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी कैम्पों पर हमला कर 22 अप्रैल का बदला लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जिसे इतिहास में 'आपरेशन सिंदूर' के नाम से जाना जाएगा। नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। चार दिन चले इस संक्षिप्त, पर भीषण युद्ध ने इस क्षेत्र में युद्ध की रूपरेखा बदल दी। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भेज दिया गया कि आतंकी हमला अदंडित नहीं जाएगा। अगर आतंक आपकी रणनीति का हिस्सा है तो इसका ज़बरदस्त जवाब देना हमारी रणनीति का है। भारत ने राष्ट्रीय शोक को राष्ट्रीय संकल्प में बदल कर जो कार्यवाही की उसी का परिणाम था कि 10 मई 2025 को दोपहर 3.35 मिनट पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का हॉटलाइन पर हमारे डीजीएमओ को फोन आया कि पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम चाहता है। दो घंटे के बाद दोनों ने युद्ध विराम का आदेश दे दिया पर पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया गया कि अगर आतंकी हमले होते रहे तो पाकिस्तान के लिए इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, 'जो किया जाएगा उसके परिणाम होंगे'। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बार-बार युद्ध समाप्त करने का श्रेय ले रहे हैं, पर हकीकत है कि युद्ध विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ था। हमारे देश में भी कुछ लोग नाखुश हैं कि युद्ध विराम क्यों किया गया जबकि पाकिस्तान की सामरिक शक्ति हम नष्ट करने में सफल हो गए थे। मैं इस आलोचना से सहमत नहीं हूं। हमारा मक़सद आतंक का जवाब देना था। यह मुरीदके और भावलपुर के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया। हमारा मक़सद उनकी जमीन हथियाना या सैनिक संस्थानों पर हमले करना नहीं था। यह हमें मजबूरन करना पड़ा। पाकिस्तान ने 8 मई की रात को आदमपुर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर पर हमले किए। आदमपुर विशेष तौर पर निशाने पर रहा। कई सौ ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान के होश ठिकाने तब आए, जब हमने उनके अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए और स्यालकोट, चकलाला, सरगोधा, रफीकी,रहीम यार खान, मुरीद को निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस की तबाही थी। यह इस्लामाबाद से केवल 10 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ को सुबह 2.30 बजे जगा कर इस हमले की विशेष सूचना दी गई। आपरेशन सिंदूर केवल 88 घंटे चला, पर पाकिस्तान को बड़े सबक दे गया। पहली बार हमने पाकिस्तान के दिल पंजाब पर हमला किया। हमने लाहौर के पास मुरीदके में हाफिज मोहम्मद सईद के लश्करे तैयबा के मुख्यालय पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। यहीं अजमल कसाब और उसके साथियों ने ट्रेनिंग ली थी। दूसरा बड़ा हमला भावलपुर में मसूद अजहर के जैश-ए -मोहम्मद के मुख्यालय पर किया गया। यह जगह सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। इसे तबाह कर संदेश दे दिया गया कि आपका कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जैसा ने हाल ही में एक पोस्ट में कहा है, वह रात भी अजीब थी। ऊपर से आग बरस रही थी। इन चार दिनों ने इतिहास बदल दिया। पूर्व राजदूत सईद अकबरुद्दीन ने लिखा है कई सालों से भारत को कहा गया कि हम शोक को संयम में परिवर्तित करें। पहलगाम के बाद हमने शोक को बदले में बदल दिया। इस देश ने पहले भी आतंकी हमले सहे हैं। सबसे बड़ा मुम्बई पर 26/11/2008 का हमला था जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने166 लोगों को मार दिया। तब यह मांग उठी थी कि जवाब दिया जाए, पर मनमोहन सिंह सरकार ने कूटनीति का रास्ता अपनाया। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने अपनी किताब 'चॉयसेज' में इस निष्क्रियता का स्पष्टीकरण यह दिया है,

नवंबर 2008 में मुम्बई पर आतंकी हमले के बारे हमने जो फ़ैसला लिया वह उस समय की सरकार को जो राष्ट्रीय हित नजर आया,के मुताबिक था। जब संसद पर 13 दिसम्बर 2001 को हमला हुआ तो भी वाजपेयी सरकार ने जवाबी कार्यवाही की जगह कूटनीति का ही सहारा लिया। कई महीने'आपरेशन पराक्रम' में सीमा पर सेना बैठा कर उसे वापिस बुला लिया गया। मेनन लिखते हैं, व्यक्तित्व मायने रखते हैं। अगर और लोग शिखर पर होते तो शायद भारत की प्रतिक्रिया और होती। वास्तव में मुझे विश्वास है कि अगर भविष्य में भारत को ऐसा ही फ़ैसला करना पड़ा तो प्रतिक्रिया अलग होगी। उनके यह शब्द भविष्य सूचक थे। अलग परिस्थिति, अलग लोग और अलग प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2025 में इतिहास बदल दिया। जो 2001 और 2008 में होना चाहिए था पर नहीं किया गया, वह कर दिया गया। भारत ने आतंक का बदला ले लिया। यह भी बता दिया कि आपकी परमाणु छतरी हमें नहीं रोकेगी और यह आपको आतंकवाद के लिए दंड से सुरक्षा नहीं देगी। चीफ़ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ़ जनरल अनिल चौहान ने एक भाषण में यह स्पष्ट कर दिया,मेरी समझ है कि परमाणु हथियार रोकने के हथियार हैं, युद्ध लड़ने के नहीं। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। पिछली सरकारों ने पाक प्रेरित आतंक का जवाब डोजियर भेज कर दिया जिन्हें किसी ने नहीं पढ़ा। हमारे संयम को हमारी कमज़ोरी और संकल्प की कमी समझा गया। हमारे पास तब भी सैनिक क्षमता थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और संकल्प का अभाव था। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (रि) लिखते हैं, सैनिक क्षमता उतनी ही कारगर होती है जितनी उसके पीछे राजनीतिक निर्देश।प्रधानमंत्री मोदी ने आपरेशन सिंदूर पर पहले घंटे से आखिरी तक बिना हिचकिचाहट और बिना शर्तों के छूट दे दी थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो हमारी सेना को राजनीतिक नेतृत्व से पूछने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान को पूरी तरह से ठोक दिया गया।

पर यह युद्ध कई सबक भी सिखा गया है। बड़ा सबक पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत का है। चीन ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले साल के अभियान के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता प्रदान की थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन निर्मित जे-10सीई लड़ाकू विमानों का ही इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें चीन सैटेलाइट से प्राप्त हमारी सैनिक तैयारी के बारे खुफिया जानकारी भी देता रहा। चीन के सरकारी मीडिया ने पहली बार एक इंजीनियर झांग हेंग का पाकिस्तान के बारे साक्षात्कार प्रसारित किया है कि, वह हमारे बीच कंधे से कंधा मिला कर, दिन-रात काम करने से बने गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। आपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर इस इंटरव्यू को प्रसारित करना खुद बड़ा संदेश है कि चीन समझता है कि पाकिस्तान को वह जो मदद दे रहा है उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। आपरेशन सिंदूर के दौरान हम उनके सैनिक सिस्टम से भी लड़ रहे थे जिसे चीन ने लैस किया है और जिसे वह गाइड कर रहे थे। डिप्टी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ ले.जनरल राहुल आर. सिंह ने स्पष्ट कहा है कि भारत की एक सीमा थी, पर विरोधी एक से अधिक थे। सेना के उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर ले. जनरल डीएस हुड्डा ने कहा है, भारत के लिए संदेश साफ़ है। पाकिस्तान के साथ भावी टकराव के समय चीन के साथ उनके व्यापक सहयोग की चुनौती के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कूटनीति और प्रचार पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। युद्ध विराम की घोषणा नई दिल्ली या इस्लामाबाद की जगह वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने की थी। प्रभाव यह गया कि हम नहीं जीते बल्कि अमेरिका ने युद्ध विराम करवाया है। पाकिस्तान का प्रचार खुद शाहबाज शरीफ़ ने सम्भाला और वह ट्रम्प को काबू करने में सफल रहे। युद्ध विराम की घोषणा नई दिल्ली में होनी चाहिए थी। अब दुनिया को इस युद्ध के बारे बहुत अस्पष्ट राय है।

पाकिस्तान के 100 के करीब सैनिक और इतने ही आतंकी मारे गए। हमारा दावा है कि उनके 13 जहाज़ नष्ट किए गए। जो हवाई अड्डों को नुक्सान हुआ वह अलग है। हमारा क्या नुक्सान हुआ जो हमला करता है उसका नुक्सान तो होता है, पर यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में जो नुक्सान हुआ उसकी तो सैटेलाइट तस्वीरें हम दिखाने में सफल रहे, पर पाकिस्तान हमारे नुक्सान की एक भी तस्वीर नहीं दिखा सका। एयर मार्शल के.भारती का कहना है कि,सवाल यह बनता है कि क्या हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का लक्ष्य पूरा किया जबरदस्त जवाब है, हां। हमारे सारे पायलट सकुशल घर लौट आए। पिछले साल मई के इन चार दिनों में भारत ने नई इबारत लिख दी। पहले रोकने पर ज़ोर दिया जाता था, अब डायरेक्ट एक्शन पर। पर क्या आपरेशन सिंदूर के बाद आतंक रुक जाएगा यहां किसी को यह आशा नहीं है। पाकिस्तान का टैरर नेटवर्क अभी भी कायम है क्योंकि उसे व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है। उनकी सेना के वजूद के लिए यह जरूरी है। आपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी सैनिक सफलता थी, पर यह अहसास है कि भविष्य में भी ऐसी चुनौती आ सकती है। हमें संक्षिप्त और लम्बे दोनों युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, जहां चीन और तुर्की उनके साथ होंगे। अमेरिका और रूस का रवैया अस्पष्ट होगा।

एमआरपी का मायाजाल- आखिर उपभोक्ता कब तक लुटता रहेगा

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत वसूलता है या बिल देने से मना करता है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता आयोग, लीगल पेट्रोलॉजी विभाग या औषधि नियंत्रक विभाग से शिकायत कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश लोग इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। इसी मुद्दे को लेकर उपभोक्ता जागरूकता अभियान चला रही संस्था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सरकार से एमआरपी व्यवस्था पर सख्त कानून बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान में एमआरपी तय करने की कोई प्रभावी सीमा या पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कंपनियां मनमाने तरीके से कीमतें निर्धारित कर रही हैं। संगठन यह भी मांग कर रहा है कि उत्पादों पर केवल एमआरपी ही नहीं, बल्कि उत्पादन लागत भी अंकित की जाए ताकि उपभोक्ता वास्तविक मूल्य को समझ सके। इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 25 मई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक धरना आयोजित करने जा रही है। संगठन का कहना है कि सरकार को एमआरपी निर्धारण, उसकी समीक्षा और नियंत्रण के लिए स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य वसूली से बचाया जा सके।

बाजार में बिकने वाली लगभग हर वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था अब कई सवालों के घेरे में है, विशेषकर दवाइयों और रोजमर्रा के उपयोग के सामानों की कीमतों को लेकर। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कंपनियां मनमाने तरीके से एमआरपी तय कर रही हैं, जिससे आम आदमी आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार एमआरपी वह अधिकतम कीमत होती है, जिस पर कोई वस्तु उपभोक्ता को बेची जा सकती है। इसमें उत्पादन लागत, पैकेजिंग, परिवहन, टैक्स और विक्रेता का लाभ शामिल होता है। एमआरपी व्यवस्था लागू होने से पहले अलग-अलग राज्यों और शहरों में एक ही उत्पाद की कीमत अलग-अलग होती थी। इसी असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने उत्पादों पर एमआरपी अंकित करना अनिवार्य किया था। लेकिन अब उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। सबसे अधिक सवाल दवाइयों की कीमतों को लेकर उठ रहे हैं। एक ही साल्ट की दवा अलग-अलग ब्रांड नामों से बाजार में कई गुना अधिक कीमत पर बेची जा रही है। जहां जन औषधि केंद्रों पर वही दवा बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होती है, वहीं निजी मेडिकल स्टोर्स पर उपभोक्ताओं को उसी दवा के लिए कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि दवा का मूल तत्व समान होने के बावजूद कीमतों में इतना बड़ा अंतर केवल ब्रांडिंग, मार्केटिंग और वितरण व्यवस्था के कारण है। बाजार में आज ऐसी स्थिति बन गई है कि कंपनियां पहले उत्पाद पर अत्यधिक ऊंची एमआरपी छापती हैं और फिर भारी छूट का दावा कर उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। उपभोक्ता को लगता है कि उसे सस्ता सामान मिल रहा है, जबकि वास्तविकता में वस्तु की मूल कीमत कहीं कम होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एमआरपी अब उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से अधिक कंपनियों के मुनाफे का माध्यम बनता जा रहा है। उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों का कहना है कि अधिकांश लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। बहुत से उपभोक्ता बिना बिल के सामान खरीद लेते हैं और बाद में शिकायत करने की स्थिति में उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता। दवाइयों के मामले में भी लोग केवल ब्रांड नाम देखकर दवा खरीद लेते हैं और उसके साल्ट या जेनेरिक विकल्प के बारे में जानकारी नहीं लेते। यही कारण है कि उपभोक्ता अक्सर अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत वसूलता है या बिल देने से मना करता है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता आयोग, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग या औषधि नियंत्रक विभाग से शिकायत कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश लोग इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। इसी मुद्दे को लेकर उपभोक्ता जागरूकता अभियान चला रही संस्था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सरकार से एमआरपी व्यवस्था पर सख्त कानून बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान में एमआरपी तय करने की कोई प्रभावी सीमा या पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कंपनियां मनमाने तरीके से कीमतें निर्धारित कर रही हैं। संगठन यह भी मांग कर रहा है कि उत्पादों पर केवल एमआरपी ही नहीं, बल्कि उत्पादन लागत भी अंकित की जाए ताकि उपभोक्ता वास्तविक मूल्य को समझ सके। इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 25 मई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक धरना आयोजित करने जा रही है। संगठन का कहना है कि सरकार को एमआरपी निर्धारण, उसकी समीक्षा और नियंत्रण के लिए स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य वसूली से बचाया जा सके। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार विशेष रूप से दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों और रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों में मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता बेहद आवश्यक है। देश में इन दिनों दवाइयों की कीमतों को लेकर गंभीर बहस छिड़ी हुई है। एक ही साल्ट की दवा अलग-अलग ब्रांड नामों से कई गुना महंगे दामों पर बेची जा रही ।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साव पब्लिकेशन एस्टे. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

सड़क से सदन तक होगा संघर्ष — ध्रुव त्रिपाठी शिक्षक विधायक

पडरौना।

संघर्ष हेतु आप सभी लखनऊ चलें — डॉ. मणिशंकर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद कुशीनगर के तत्वावधान में आज हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज, पडरौना में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों के सम्मान तथा नवनियुक्त प्रधानाचार्य साथियों के अभिनंदन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय संरक्षक डॉ. टी.पी. सिंह ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. मणिशंकर तिवारी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के पूर्व महामंत्री डॉ. रविंद्र त्रिपाठी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने उद्बोधन में शिक्षक विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आज प्रदेश का तदर्थ प्रधानाचार्य स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लंबे समय से प्रधानाचार्य पद का दायित्व निभाने के बावजूद सरकार उनके स्थायीकरण को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अनेक प्रधानाचार्य सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं, फिर भी सरकार की हठधर्मिता के कारण उनका स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. मणिशंकर तिवारी ने समस्त प्रधानाचार्यों का आह्वान करते हुए कहा कि जून माह में सभी लोग लखनऊ पहुंचें, वहीं से संघर्ष का शंखनाद होगा और प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रांतीय संरक्षक डॉ. टी.पी. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने सदैव संघर्ष के बल पर उपलब्धियां प्राप्त की हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सरकार अंततः प्रधानाचार्यों की पीड़ा को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भगवान हनुमान जी के चित्र पर पुष्पार्चन एवं माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। जिला अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र मोदी त्रिपाठी ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया तथा संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। स्वागताध्यक्ष प्रांतीय महामंत्री शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि जब-जब आवश्यकता पड़ी है, संघर्ष से ही सृजन का मार्ग निकला है। उन्होंने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों से संगठन के निर्देशानुसार आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पूर्व महामंत्री डॉ. रविंद्र त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद प्रधानाचार्यों को अकेश्चक के रूप में लगाए जाने के विरुद्ध परिषद ने संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप शासन को निर्णय बदलना पड़ा। उन्होंने संगठन की एकजुटता को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम के अंत में जनपद संरक्षक डॉ. गोरख राय ने आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि प्रबंधक वर्ग भी उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संघर्ष की हर परिस्थिति में सहयोग करेगा। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री अश्विनी कुमार पडिय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं नवनियुक्त प्रधानाचार्यों में सुनील कुमार मिश्रा, अनिल सिंह, विष्णु प्रसाद शिवम एवं कुलदीपक सिंह सहित इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए लगभग 20 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को जनपद कोषाध्यक्ष अशोक कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की उपस्थिति अत्यंत सराहनीय एवं उत्साहवर्धक रही। कार्यक्रम में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ विजय राय , राजीव मल्ल सहित शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

युवती को अगवा कर अस्पताल में बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक युवती को जबरन उठाकर निजी अस्पताल के कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल से मुक्त कराया। युवती ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता के अनुसार पांच मई को वह अपनी सहेली के घर पड़ोसी गांव गई थी। आरोप है कि रात में सहेली के भाई ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण युवती ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी। आरोप है कि बुधवार सुबह युवती घर पर अकेली थी, तभी आरोपी युवक उसके घर में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। इसी दौरान युवती की मां मौके पर पहुंच गईं। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब युवती घर से कुछ दूरी स्थित घोटा की ओर जा रही थी, तभी आरोपी अपने एक साथी के साथ पहुंचा और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर कोटवा स्थित एक निजी अस्पताल में ले गया। आरोप है कि वहां कमरे में करीब तीन घंटे तक उसे बंद कर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने किसी तरह अस्पताल में मौजूद एक नर्स के मोबाइल से डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल से मुक्त कराया, जबकि आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंदभूषण प्रजापति ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राप्त हो गई है तथा मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जनपदीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक आयोजित

कुशीनगर।

महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), तहसीलदार हाटा, तहसीलदार तमकुहीराज, तहसीलदार कसया, तहसीलदार पडरौना, तहसीलदार खड्डा तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

इबैठक के दौरान जनपद से संबंधित चार प्रकरणों की सुनवाई की गई। प्रत्येक मामले में पक्ष एवं विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जाति संबंधी विवादों का निस्तारण सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाए।

उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों एवं संबंधित प्रकरणों की तहसीलदार स्वयं गहन जांच करें तथा आवेदक के सामाजिक, पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए स्थलीय सत्यापन के बाद शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र आवेदन को स्वीकृत अथवा निरस्त किया जाता है तो उसके संबंध में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक कारण अंकित किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्णय शासनादेशों में वर्णित प्रावधानों, स्थलीय जांच एवं सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर ही लिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों में वादी अथवा प्रतिवादी द्वारा जनता दर्शन अथवा समाधान दिवस में शिकायत प्रस्तुत करना निर्धारित शासकीय प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति है, तो शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जनपदीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जनपदीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर संबंधित व्यक्ति मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मंडलीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष अपील कर सकता है। मंडलीय समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित राज्य जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी। राज्य समिति के निर्णय से भी असंतुष्ट होने पर संबंधित व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित सभी प्रकरणों का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए।

सीएम योगी की अपील का असर, महापौर ने छोड़ी स्कॉर्ट वेहिकल

गोरखपुर।

सांसद रविकिशन ने भी छोटा कर दिया अपना काफिला
जीडीए उपाध्यक्ष ने भी स्कॉर्ट वाहन को हटाया
ईंधन संरक्षण और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर काफिले में कटौती सहित अन्य ऐहतियातों की आवश्यकता जताई है मुख्यमंत्री ने

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भविष्योन्मुखी बहुआयामी प्रभाव के मद्देनजर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने तथा सरकारी खर्चों में कटौती करने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश/अनुरोध का असर दिखने लगा है। सीएम योगी की अपील का अनुसरण करते हुए गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अब बिना स्कॉर्ट वाहन के आना-जाना शुरू कर दिया है। सांसद रविकिशन शुक्ल ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। अब वह दो गाड़ियों के साथ ही निकल रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद अपने कार्य दायित्व निर्वहन के लिए स्कॉर्ट वाहन को हटा दिया है। इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी शीघ्र ही सप्ताह में एक दिन 'नो वेहिकल डे' अपनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधियों और उच्च पदस्थ अफसरों के काफिलों में 50 प्रतिशत तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसका अनुपालन भी शुरू कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद राज्य में सप्ताह में एक दिन नो वेहिकल डे रखने, बड़े कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने और 50 फीसदी बैठकों को वर्चुअल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ सार्वजनिक परिवहन और बिजली बचत को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। बिजली की बचत के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का आह्वान किया है। स्कॉर्ट वाहन के बिना चलने के संबंध में गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण को पीएम मोदी और सीएम योगी ने आर्थिक आवश्यकता के साथ ही राष्ट्रीय दायित्व भी माना है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन को जुड़ना होगा। इस बीच सांसद रविकिशन शुक्ल ने भी अपने काफिले में समर्थकों की गाड़ियों को मना कर दिया है। सांसद ने लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान की गहराई को समझें। पीएम और सीएम की अपील बेहद दूरदर्शी है।

ई रिक्शा और बस से यात्र की देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील का असर देवरिया में भी देखा गया। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने गुरुवार को अपने गांव जाने के लिए सरकारी वाहन की बजाय ई रिक्शा और बस से यात्रा की। श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान को समय की मांग बताया। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे परिवहन के लिए सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें। उधर, बुधवार को महराजगंज में सदर विधायक भी ई रिक्शा से जिला मुख्यालय पहुंचे थे।

आईसीयू में हुई शादी- घायल दुल्हन की मांग में दूल्हे ने भरा सिंदूर, रिश्तों की मिसाल बना गोरखपुर

गोरखपुर। वर्ष 2006 में आई सूरज बड़जात्या की चर्चित फिल्म विवाह का भावुक दृश्य शायद ही किसी ने भुलाया हो, जब हादसे में घायल दुल्हन की मांग में दूल्हा अस्पताल में सिंदूर भरता है। कुछ ऐसी ही मार्मिक और भावुक तस्वीर गोरखपुर में देखने को मिली, जहां आईसीयू में भर्ती दुल्हन की मांग में दूल्हे ने सिंदूर भरकर रिश्तों की नई मिसाल पेश कर दी। मामला बांसगांव क्षेत्र के हटगांव निवासी पूजा यादव का है, जिनकी शादी 13 अप्रैल को तय थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और पूजा भी नई जिंदगी के सपने संजो रही थीं। इसी बीच एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देकर भाई के साथ लौटते समय अचानक पूजा को चक्कर आ गया और वह बाइक से गिर पड़ी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गईं। आनन-फानन में पूजा को शहर के दाउदपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आईसीयू में निगरानी में रखा। इधर, शादी की तारीख नजदीक थी। दोनों परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, लेकिन रिश्तों की मजबूती और विश्वास ने हालात के आगे हार नहीं मानी। आपसी सहमति से तय किया गया कि शादी तय मुहूर्त पर ही होगी। महादेवा बाजार के महुआ निवासी दूल्हे सन्नी यादव बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचे। पारंपरिक रस्में निभाने के बाद सन्नी सीधे अस्पताल पहुंचे और आईसीयू में भर्ती पूजा यादव की मांग में सिंदूर भरकर सात जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। इस भावुक दृश्य को जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। दुल्हन के भाई का रो-रोकर बुरा हाल था, जबकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, स्टाफ और परिजन इस अनोखी शादी के साक्षी बने। डॉक्टरों ने बताया कि पूजा की हालत में पहले से सुधार है और पूरी टीम उन्हें जल्द स्वस्थ करने में जुटी है। डॉक्टरों ने कहा कि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसा दृश्य देखा है, जहां रिश्तों की संवेदनशीलता और समर्पण ने हर किसी को भावुक कर दिया। यह घटना न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी पर टिप्पणी निंदनीय, शिक्षकों को आत्ममंथन की जरूरत - अरविन्द कुमार चन्द

गोरखपुर। बीआरसी उरुवा में आयोजित शिक्षक समूह की बैठक में ब्लाक अध्यक्ष अरविन्द कुमार चन्द ने कहा कि बीते दिनों एक समूह द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कुछ लोगों ने स्वयं को गिरे हुए शिक्षकों की श्रेणी में खड़ा कर लिया है। चन्द ने कहा कि कथित रूप से आरोप लगाने वाले शिक्षकों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने बताया कि उरुवा के खण्ड शिक्षा अधिकारी लगातार विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता, साफ-सफाई, छात्र नामांकन, छात्र उपस्थिति एवं अभिभावकों के साथ बैठक जैसे विषयों की गंभीरता से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास कुछ शिक्षकों को नागवार गुजर रहे हैं, जिसके चलते अपरिपक्व एवं अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए शिक्षकों से मर्यादा और जिम्मेदारी का पालन करने की अपील की।

पत्रकारिता समाज को सही दिशा देने का सशक्त माध्यम - सबीना मैडम

गोरखपुर।

असबाबे हिंदुस्तान एवं आईन-ए-मुल्क उर्दू अखबार की संपादक सबीना मैडम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मीडिया कार्यालय में ब्यूरो प्रमुख इसरार अंसारी ने उन्हें सफेद साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया तथा प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो भेंट किया। सम्मान समारोह के दौरान इसरार अंसारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं संपादक सबीना मैडम ने अपने संबोधन में कहा कि एक पत्रकार के लिए उसकी पत्रकारिता ही उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है।

उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही दिशा देने का कार्य करता है और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इस मौके पर दबीर अब्बास ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पत्रकारों को अपनी एकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को बाजारवाद से बचाते हुए बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने की दिशा में गंभीर पहल करने की जरूरत है।

सीलिंग से डरे दुकानदारों के बीच पहुंचे बीजेपी विधायक, व्यापारियों को कार्रवाई न होने का भरोसा दिया

नई दिल्ली। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में इन दिनों सीलिंग को लेकर जबरदस्त डर और असमंजस का माहौल बना हुआ है। डीडीए और एमसीडी की संभावित कार्रवाई के डर से कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे ईंट की दीवारें तक खड़ी कर दीं, ताकि दुकानें सील होने से बच सकें। लेकिन अब इलाके के बीजेपी विधायक और पार्षद मैदान में उतर आए हैं और दुकानदारों को भरोसा दिला रहे हैं कि फिलहाल कोई सीलिंग नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत न्यू अशोक नगर की सैकड़ों दुकानों को नोटिस जारी किए हैं। आरोप है कि रिहायशी इलाके में कई लोगों ने अपनी दुकानों के सामने व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसी के चलते इलाके में कभी भी डीडीए, नगर निगम और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही थी। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में ऐसा डर बैठ गया कि न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन रोड और चिल्ला सरोदा बांगर इलाके में कई लोगों ने अपनी दुकानों के सामने ईंट की दीवार खड़ी कर ली। उनका मानना था कि अगर दुकान पूरी तरह बंद दिखेगी तो शायद सीलिंग की कार्रवाई टल जाए और उनका रोजगार बच सके। इसी बीच त्रिलोकपुरी से बीजेपी विधायक रविकांत उज्जैनवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में विधायक रविकांत ने कहा कि जनता हमारा परिवार है। किसी भी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई रुक गई है और इसे रुकवाने में मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा की भी बड़ी भूमिका रही है। विधायक ने दुकानदारों से कहा कि वे अपनी दुकानों के सामने बनाई गई दीवारें हटा लें और दोबारा दुकानें खोलें। मौके पर विधायक खुद लोगों को समझाते नजर आए। कई दुकानदार उनके भरोसे के बाद मान भी गए और उन्होंने अपनी दुकानें फिर से खोलनी शुरू कर दीं। हालांकि कुछ दुकानदार अभी भी डरे हुए हैं और खुलकर सामने आने को तैयार नहीं हैं। विधायक रविकांत ने कहा कि वह लोगों के पास गए और उनसे कहा कि दीवार हटाकर दुकान खोलिए, हम आपके साथ हैं, कोई सीलिंग नहीं होगी। जो लोग अभी नहीं मान रहे हैं, उन्हें भी समझाया जाएगा। वहीं बीजेपी पार्षद संजीव कुमार भी इलाके में पहुंचे और उन्होंने भी दुकानदारों को आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं, पार्षद संजीव खुद छेनी-हथौड़ी लेकर दुकानों के सामने बनी दीवारें तोड़ते नजर आए। उनका कहना था कि सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है और किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इलाके की ज्यादातर दुकानें पुरानी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कानूनी रूप से नोटिफाई कराने की प्रक्रिया भी शुरू कराई जाएगी। उनका दावा है कि व्यापारी जो भी जरूरी शुल्क होगा, वह जमा कराने को भी तैयार हैं।

19 राज्य-यूटी में एसआईआर का ऐलान

नई दिल्ली।

- **यहां 37 करोड़ वोटर्स**
- **30 मई से 23 दिसंबर के बीच होगा वेरिफिकेशन**
- **पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल चुनाव**

चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसके तहत देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, जनगणना के तहत चल रहे गृह-सूचीकरण प्रक्रिया के साथ साझा जमीनी तंत्र को ध्यान में रखते हुए एसआईआर के तीसरे चरण का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। आयोग के अनुसार, एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम मई 2026 से शुरू होकर दिसंबर 2026 तक चलेगा और अलग-अलग राज्यों में अंतिम मतदाता सूची सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच प्रकाशित की जाएगी।

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाद में होगा एसआईआर

आयोग ने बताया कि एसआईआर का तीसरा चरण पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इसमें कवर हो जाएगा। आयोग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मतदाता सूची के कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी, जिसमें बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि, मतदाता सूची के तीसरे चरण में दिल्ली को शामिल किया जाएगा, जहां 7 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

भारत के दो एलपीजी वाहक जहाजों ने पार किया होर्मुज; भारतीय झंडा लगा जहाज हमले के बाद डूबा

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान तनाव के बीच दो और भारतीय ध्वज वाले एलपीजी जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई। एलपीजी जहाज सिमी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के दौरान अपने ट्रांसपोंडर को कुछ समय तक बंद रखने के बाद गुरुवार को ओमान की खाड़ी में देखा गया। अन्य एलपीजी जहाज एनवी सनशाइन ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के दौरान कुछ ऐसा ही किया। यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है, जब पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका में तनाव बना हुआ है और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को स्वैप रिफाइनरी से एलपीजी से लदा एनवी सनशाइन जहाज को आखिरी बार भारत के मंगलौर की ओर जाते हुए देखा गया था। इसी बीच, सिमी कतर के रस लाफान बंदरगाह से गुजरात के कांडला तक ईंधन ले जा रहा है। भारतीय ध्वज वाला जहाज हाजी अली, जो एक पारंपरिक ढाउ या मोटर चालित नौका थी, सोमालिया से यूएई के शारजाह जा रहा था। इसी दौरान बुधवार तड़के ओमान के जलक्षेत्र में उस पर हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और बाद में वह डूब गया। इस घटना की पुष्टि बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने की। ओमान के तट पर भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुए हमले के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कल ओमान के तट पर भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। भारत दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों को खतरे में डालना, या किसी भी तरह से नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता में बाधा डालना, पूरी तरह से टाला जाना चाहिए।

खत्म हुआ सस्पेंस! वीडी सतीशन बने केरलम के नए मुख्यमंत्री

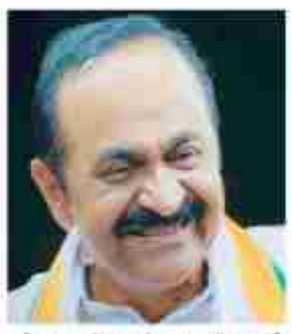

केरल। केरल के नए सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। वीडी सतीशन को राज्य का नया सीएम बनाया गया है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के पार्टी आलाकमान के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को पूरे राज्य में जश्न का माहौल छा गया। जब कांग्रेस नेताओं ने नयी दिल्ली में उनके नाम की घोषणा की तब सतीशन तिरुवनंतपुरम स्थित कंटोनमेंट हाउस में थे, जो विपक्ष के नेता का आधिकारिक आवास है। घोषणा के तुरंत बाद सतीशन के समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई और उन्होंने राज्य के कई हिस्सों में पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटीं। एर्नाकुलम जिले के परवुर में भी बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया जहां से वह 2001 से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सतीशन को इस पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था और चयन प्रक्रिया के दौरान यूडीएफ के सहयोगी दलों ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। सतीशन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल को भी इस पद का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था।

सीबीआई के रडार पर एनटीए के अधिकारी, पेपर लीक मामले में पूर्व शिक्षक समेत दो और गिरफ्तार

एजुकेशन डेस्क। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच तेज करते हुए दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उन संस्थानों के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है, जिन्हें प्रश्नपत्र छपाई से जुड़ी प्रक्रिया तक पहुंच प्राप्त थी। सीबीआई ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के लातूर से एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर को भी हिरासत में लिया गया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर के 14 स्थानों पर छापेमारी भी की है। जांच एजेंसी फिलहाल पेपर लीक के असली स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, अब तक की जांच में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले एजेंसी जयपुर से मांगीलाल बीवाल, विकास बीवाल और दिनेश बीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा गुरुग्राम के यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार को भी पकड़ा गया था।

10 से 12 लाख रुपये देने को तैयार था मांगीलाल बीवाल

जांच में सामने आया है कि शुभम खैरनार ने अप्रैल महीने में यश यादव को जानकारी दी थी कि मांगीलाल बीवाल अपने छोटे बेटे के लिए लीक हुए नीट प्रश्नपत्र के बदले 10 से 12 लाख रुपये तक देने को तैयार है। आरोप है कि खैरनार ने यादव को 500 से 600 सवाल उपलब्ध कराए थे, जिनमें से कई असली परीक्षा में आए।

रिश्तेदारों में भी बांटा पेपर

सीबीआई के मुताबिक, मांगीलाल बीवाल ने यही पेपर अपने बेटे और रिश्तेदारों में भी बांटा था। एजेंसी को डिजिटल उपकरणों की जांच में कई चैट, लीक प्रश्नपत्र और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। अब इन डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच कर डिलीट डेटा भी निकाला जाएगा।

मॉक टेस्ट से 42 सवाल परीक्षा में आए

इसी बीच, महाराष्ट्र के लातूर में भी जांच तेज हो गई है। लातूर को कोचिंग हब माना जाता है, जहां राज्यभर से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। यहां एक छात्र के अभिभावक ने शिकायत की थी कि एक निजी कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट के 42 सवाल नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खाते थे। इसके बाद सीबीआई ने लातूर के एक कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक को हिरासत में लिया है। हालांकि, एजेंसी ने अभी उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। इससे पहले लातूर पुलिस कोचिंग स्टाफ, काउंसलर और छात्रों समेत छह लोगों से पूछताछ कर चुकी है। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी थी। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी दावा किया था कि परीक्षा से पहले प्रसारित एक गेस पेपर के लगभग 120 सवाल वास्तविक परीक्षा में आए थे।

यूपी में आंधी-तूफान, 104 लोगों की मौत

लखनऊ। देश में दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज-अयोध्या समेत 30 जिलों में बुधवार को आंधी-तूफान के कारण 104 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुईं। यहां 80 किमी की रफ्तार से आंधी चली, बरेली में एक शख्स टीनशेड समेत हवा में उड़ गया। राज्य के बांदा शहर में तापमान 45.4°C रहा। आज 51 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी तेज गर्मी और हीटवेव का असर है। लगातार चौथे दिन राज्य का जैसलमेर देश का सबसे गर्म शहर रहा, यहां 46.1°C तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज आज बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट है। 13 जिलों में हीटवेव की चेतावनी है।

एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत, मची चीखपुकार

बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे वाहन में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) पलाश बंसल ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के रथौरा गांव के नजदीक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

कोलकाता के डीसीपी पर ईडी का शिकंजा- डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा गिरफ्तार; पूर्व मुख्यमंत्री ममता से थी करीबी

नई दिल्ली। कोलकाता से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को एक कथित वसूली रैकेट में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एक संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े मामले की जांच के दौरान की गई, जिसमें कुख्यात अपराधी सोना पप्पू और व्यवसायी जय कामदार के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और इसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है। जांच एजेंसी के अनुसार, डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद वह खुद के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए। हालांकि, जांच के दौरान उन पर सहयोग न करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया। ईडी अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह पूरा मामला कथित रूप से एक बड़े वसूली रैकेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें अपराधी सोना पप्पू और व्यवसायी जय कामदार के बीच आर्थिक लेन-देन और अवैध वसूली के नेटवर्क की जांच चल रही थी। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क में कुछ प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका हो सकती है, जिसके चलते मामले की जांच को और गहराई से आगे बढ़ाया जा रहा है। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के जरिए कथित रूप से अवैध धन की वसूली और उसे अलग-अलग माध्यमों से घुमाने की कोशिश की गई।

जांच में असहयोग का आरोप

ईडी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि गिरफ्तार अधिकारी से पूछताछ के दौरान असहयोग की स्थिति बनी रही। एजेंसी का दावा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया, ताकि आगे की पूछताछ और सबूतों की जांच प्रभावी ढंग से की जा सके।

सियासी करीबी और बढ़ती मुश्किलें

बताया जाता है कि शांतनु सिन्हा का संबंध तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व, खासकर ममता बनर्जी से करीबी रहा है। उन पर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं। अब राज्य की सत्ता बदलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।

पीएम की अपील का असर- बाइक से विधान भवन पहुंचे सीएम फडणवीस

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। इसी क्रम में कई मंत्रियों ने अपने काफिले के आकार को कम कर दिया है। वहीं, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को विधान भवन मोटरसाइकिल से पहुंचे। वहां वह नए विधान परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद उठाए गए उपायों का हिस्सा है। फडणवीस अपने आवास वर्षा से मोटरसाइकिल पर दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन पहुंचे। उनके साथ भाजपा नेता और मंत्री आशीष शेलार भी थे। ईंधन बचाने के उद्देश्य से इसी तरह का एक कदम उठाते हुए राज्य मंत्री नितेश राणे ने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय (राज्य सचिवालय) तक पैदल जाना चुना। बुधवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने कई मितव्ययिता उपायों की घोषणा की, जिनमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के काफिले में वाहनों की संख्या को आधा करना और मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरों को रद्द करना शामिल है।

नेता विपक्ष की भूमिका बस दिखावा- सीईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम टिप्पणी, पूछा पैनल में स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं

नई दिल्ली। देश में चुनाव आयोग के शीर्ष पदों मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि मौजूदा चयन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रभाव इतना अधिक दिखाई देता है कि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति प्रक्रिया तय की गई है। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और मामले को अगली तारीख पर आगे विचार किया जाएगा।

चयन समिति पर उठाए सवाल

वर्तमान कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसी संरचना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें किसी भी स्वतंत्र सदस्य को शामिल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि इस व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया लगभग तय हो जाती है, क्योंकि दो सदस्य सरकार से जुड़े होते हैं और तीसरे सदस्य का प्रभाव सीमित रह जाता है।

विपक्ष का नेता केवल औपचारिक भूमिका में

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चयन समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि चयन समिति में विपक्ष के नेता की भूमिका केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाती है। कोर्ट ने सवाल किया कि यदि अंतिम निर्णय 2-1 के अनुपात में पहले से ही तय है, तो इस समिति में संतुलन का दावा कितना वास्तविक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी कैबिनेट मंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ जाएगा।

आयोग केवल स्वतंत्र नहीं दिखना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि केवल स्वतंत्रता का दावा पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता वास्तविक और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देनी चाहिए। कोर्ट ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और इसके लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता अनिवार्य है।

सरकार का पक्ष- कानून पर संसद का अधिकार

केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और इसे अदालत में केवल संभावित आशंकाओं के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश अंतरिम व्यवस्था थे, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को बाधित नहीं कर सकते। सरकार के वकील ने यह भी तर्क दिया कि जब तक यह साबित न हो जाए कि चुनाव आयोग वास्तव में पक्षपाती है, तब तक कानून को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।

स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं जोड़ा गया?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहा कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को ही शामिल किया जाए, लेकिन सवाल यह जरूर है कि कोई भी स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं रखा गया। अदालत ने कहा कि अन्य संस्थाओं में, जैसे जांच एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं, तो चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया गया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका काम नीति बनाना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या 2023 का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 के अनुरूप है या नहीं।

मामला बड़ी पीठ को भेजने पर चर्चा

सुनवाई के दौरान इस मामले को संविधान पीठ (पांच जजों की बड़ी बेंच) को भेजने पर भी विचार हुआ, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और 324 की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है। हालांकि, इस पर सभी पक्षों में सहमति नहीं बन सकी और सुनवाई को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के तहत नियुक्तियों में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन बाद में संसद ने नया कानून पारित कर इस समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।